महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – उन्नासीवां संस्करण (माह अक्टूबर, 2022)

''पहल'' के इस संस्करण में ....

1. अपनी बात ....
2. भारत रत्न नानाजी देशमुख की 106 वीं जयंती पर चार दिवसीय ग्रामोदय मेला व शरदोत्सव का शुभारंभ
3. अधोसंरचना युक्त ग्रा.पंचा. शाहपुर, नरसिंहपुर
4. प्रदेशव्यापी नशामुक्ति अभियान
5. मध्यप्रदेश ग्रामीण परिवहन सेवा : ग्रामोत्थान की दिशा में एक सार्थक प्रयास
6. बैतूल, ज.पं. आमला की ग्रा.पं. बोरदेही में निष्काषित अपशिष्ट जल का शुद्विकरण कार्य
7. स्व–सहायता समूह की सफलता की कहानी
8. ''हमारा गांव भी बनेगा तालो का ताल''
9. मुझे मिला राजमिस्त्री प्रशिक्षण से रोजगार
10. प्रशिक्षण से मेसन जीवन में सकारात्मक परिवर्तन
11. कार्यशैली से बिजावर जिला छतरपुर प्रदेश ने रचा इतिहास
12. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बढ़ते कदम

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार	प्रधान संपादक
श्री उमाकांत उमराव (IAS) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री संजय कुमार सराफ, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्रीमती सुनीता चौबे,

उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com

Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई—न्यूज लेटर का उन्नासीवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2022 का आठवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में सतना जिले में प्रसिद्ध तपोस्थली चित्रकूट में भारत रत्न नाना जी देशमुख की 106 वीं जयंती पर दिनांक 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार से 4 दिवसीय ग्रामोदय मेला एवं शरदोत्सव का शुभारंभ केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उच्च शिक्षा, श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा नानाजी मंडप के सामने नाना जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। जिसे **''भारत रत्न नानाजी देशमुख की कर्मभूमि चित्रकूट में उनकी 106 वीं जयंती पर चार दिवसीय ग्रामोदय मेला व शरदोत्सव का शुभारंभ''** आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इससे साथ ही **''सफलता की कहानी – मध्यप्रदेश के जिला नरसिंहपुर में अधोसंरचना युक्त ग्राम पंचायत शाहपुर'', ''प्रदेशव्यापी नशामुक्ति अभियान'', ''मध्यप्रदेश ग्रामीण परिवहन सेवाः ग्रामोत्थान की दिशा में एक सार्थक प्रयास'', ''बैतूल की जनपद पंचायत आमला की ग्राम पंचायत बोरदेही में प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर स्ट्रक्चर से निष्काषित अपशिष्ट जल का शुद्विकरण कार्य'', ''स्व—सहायता समूह के माध्यम से नलजल योजना के संचालन के सफलता की कहानी'', ''हमारा गांव भी बनेगा तालो का ताल'', ''मुझे मिला राजमिस्त्री प्रशिक्षण से रोजगार'', ''मेसन प्रशिक्षण से आवास के लाभार्थी एवं मेसन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन'', ''कार्यशैली से बिजावर जनपद पंचायत जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास''** एवं **''राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बढ़ते कदम''** आदि आलेखों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

भारत रत्न नानाजी देशमुख की कर्मभूमि चित्रकूट में उनकी 106 वीं जयंती पर चार दिवसीय ग्रामोदय मेला व शरदोत्सव का शुभारंभ

सतना जिले में प्रसिद्ध तपोस्थली चित्रकूट में भारत रत्न नाना जी देशमुख की 106 वीं जयंती पर दिनांक 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार से 4 दिवसीय ग्रामोदय मेला एवं शरदोत्सव का शुभारंभ केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उच्च शिक्षा, श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा नानाजी मंडप के सामने नाना जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान ने कहा कि राजनीति में रह कर समाज नीति की नई परिभाषा नानाजी ने दी है। नानाजी ने चित्रकूट में मुक्त विश्वविद्यालय की कल्पना को साकार रूप दिया है कि लोग आएँ सीखे, समझे और आत्म–सात कर अपने जीवन में उतारें।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, उत्तराखंड सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मध्यप्रदेश के खनिज मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री ऊषा ठाकुर, उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री राकेश सचान, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर श्री जयवीर सिंह, लोकसभा सदस्य सतना श्री गणेश सिंह, लोकसभा सदस्य बांदा चित्रकूट श्री आर.के. सिंह पटेल, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष श्रीमती इमरती देवी, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री अनिल कोठारी, जन अभियान परिषद मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र जामदार, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान,

मध्यप्रदेश, जबलपुर के संचालक श्री संजय कुमार सराफ एवं दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान श्री अतुल जैन प्रमुख रूप से मंचासीन रहे। मंच के बाँयी तरफ संतों के लिए अलग से मंच बनाया गया था, जिसमें चित्रकूट के सभी प्रमुख संत–महात्मा मंचासीन रहे।

केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी का सौभाग्यशाली है जो कि चित्रकूट में राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर इस कार्यक्रम में शामिल होने का हमें मौका मिला। चित्रकूट 21वीं शताब्दी की ओर 1 नया रूप ले रहा है, जहां गांवों में पढाई कैसे हो संस्कार कैसे हो, इस पर दीनदयाल शोध संस्थान रोल मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है। पोलियो की टीका लगाने में हमें 30 साल लग गये परंतु आज हमने कोरोना के टीके के 225 करोड़ डोज केवल 2 साल में लगा दिये हैं। इसके अलावा डिजीटल इंडिया के तहत आने वाले 2 साल के अंदर हर गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ जायेगा। हम ग्राम पंचायत से शहर क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, चिकित्सा के लिए, आज डिजिटल इंडिया के चलते हम दुनिया के अच्छे–अच्छे चिकित्सक से हम गांव में ही बैठकर परामर्श कर सकेगें। भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए गांव को आत्म निर्भर बनाना जरूरी है। कोविड–19 में हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 150 देशो में कोविड–19 की डोज पहुंचाई है।

अध्यात्म भारतीय संस्कृति की रीढ़ पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जैसी भूमि पूरे विश्व में कहीं नहीं है। राष्ट्र ऋषि नाना जी गांव को स्वावलंबी बनाना इसलिए चाहते थे क्योंकि देश की आत्मा गांव में बसती है। 21वीं सदी का भारत आत्म निर्भर भारत हो, स्वावलंबी भारत हो। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं 1 जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। उन्होने कहा कि अध्यात्म भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। भारतीय संस्कृति विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है। आने वाले पीढ़ी को इसे जीवन में उतार कर वैदिक पद्धति अपनाना होगा, ताकि वे अपना भविष्य सुरक्षित और सुखमय बना सकें।

बृजेंद्र प्रताप सिंह खनिज संसाधन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने भाषण में कहा कि राष्ट्र ऋषि नाना जी का चरित्र हमारे जीवन के लिए एक सीख है। नाना जी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और गांवों को लेकर बहुत कार्य किया है। उन्होने ग्रामोदय की जो अलख जगाई, उसे ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श के रुप में अपनाया तथा राष्ट्रऋषि ने अपने विचारों और मूल्यों से कभी भी समझौता नहीं किया।

सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा 90 के दशक में जब नाना जी चित्रकूट आए तो उन्होंने ग्राम विकास का ऐसा मॉडल खड़ा किया जिसने लोगों के लिए स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया। जो मॉडल नाना जी ने खड़ा किया यह पूरे भारत के गांव के लिए है, मैं सभी अन्य राज्यों के मंत्री गणों से भी आग्रह करूंगा। यह मॉडल सभी राज्यों के ग्रामों तक अनुकरणीय बने। आयोजन को उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत, सांसद बांदा आर.के. सिंह पटेल, उत्तरप्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, ने भी संबोधित किया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि आत्म–निर्भर भारत के सपने को साकार करने में दीनदयाल शोध संस्थान देश में एक रोल मॉडल है। आज जल उपलब्धता की दिशा में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वह आने वाले 50 वर्ष में बढ़ती आबादी के लिये पीने के पानी की आपूर्ति और जल–संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। वर्ष 2047 तक हम आजादी का शताब्दी वर्ष एक विकसित भारत के रुप में मनायेंगे।

ठाकुर जयवीर सिंह संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उद्बोधन में कहा कि दो प्रांतो की सीमाओं में रहकर ग्रामोदय से राष्ट्रोदय का सपना साकार हो रहा है। राकेश सचान मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आज स्व सहायता समूह के माध्यम से देश की महिलाओं को रोजगार के नये अवसर प्रदान हो रहें हैं।

बांदा चित्रकूट सांसद आर के सिंह पटेल ने कहा कि नानाजी ने जो सपना देखा था वह अब व्यापक रूप ले चुका है। नानाजी भले ही शरीर से आज हमारे बीच न हों पर ये ग्रामोदय मेला इस बात का सदैव एहसास कराता हैं कि नानाजी आज भी हमारे पास है।

इस दौरान दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव अतुल जैन ने अपने विचार रखते हुए कहा कि भारतीय विचार में पंच'ज' यानी पांच महाभूत जिसमें जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर ये सभी भगवान के द्वारा दी गई अमूल्य भेंट हैं, और इनका संवर्धन करने पर संपूर्ण सृष्टि का विकास होगा, और इसके लिए एकात्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दीनदयाल शोध संस्थान पंचज के प्रमुख घटक जल पर प्रमुखता से काम कर रहा है, सुजलाम–जल संस्कृति सेमिनार उसी का एक हिस्सा है।

कार्यक्रम का संचालन दीनदयाल शोध संस्थान के महाप्रबंधक श्री अमिताभ वशिष्ठ द्वारा किया गया। कार्यक्रम की भूमिका संगठन सचिव श्री अभय महाजन द्वारा रखी गई। अतिथियों का स्वागत डीआरआई के उपाध्यक्ष श्री निखिल मुंडले एवं श्री उत्तम बनर्जी द्वारा किया गया।

रविवार शाम सुरेन्द्रपाल ग्रामोदय विद्यालय खेल प्रांगण के कार्यक्रम में आयोजित देश की मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर ने मुख्यमंच से समां बांध दिया। अपने सुरीले लोकगीतों से नगर वासियों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। सूफी गीत और भजनों की प्रस्तुति से उन्होंने माहौल में रंग लाने की रही–सही कसर भी पूरी कर दी। महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में सुर–संगीत कद्रदान उमड़े और लोकगीतों पर जमकर झूमे।

इस कार्यक्रम की विस्तृत रूप रूपरेखा के बारे में जनसम्पर्क अधिकारी राजेश बैन जी ने बताया कि ग्रामोदय मेले के लिए तीन अलग–अलग डोम तैयार किये गए है। पहले डोम को नानाजी मंडप नाम दिया गया

है जिसमें 'एक जिला–एक उत्पाद' पर विशेष प्रदर्शनी होगी। मध्यप्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख उत्पादों को उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरे डोम का नाम दीनदयाल मंडप होगा, मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के लिए प्रमुख कार्यक्रम, गतिविधियों, योजनाओं, नीतियों आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। तीसरा अब्दुल कलाम मंडप होगा, जिसमें केन्द्र शासन के मंत्रालय/उपक्रम तथा निजी कंपनियों संबंधी प्रदर्शनी होगी। चार दिवसीय मेले में विभिन्न विषयों पर सेमीनार, परिचर्चा, गोष्ठियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।

प्रथम दिवस 9 अक्टूबर 2022 रविवार को मेला परिसर में शुभारंभ एवं मुख्य अतिथियों के उद्बोधन पश्चात मुख्य पंडाल में ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, जनप्रतिनिधियों सरपंच सम्मेलन, सुजलाम–जल संस्कृति, प्राकृतिक खेती क्रेता–विक्रेता सम्मेलन, जनजातीय समुदाय के पोषण एवं उत्तम स्वास्थ्य में फलों का महत्व, बाल संरक्षण अधिकारों पर जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन और सेमिनार का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों (सरपंचों) की सेमिनार, मंदाकिनी भू–क्षरण रोक के लिए निर्माण कार्य का पंचवटी घाट पर भूमि पूजन, मूल्य सहायता प्राप्त खाद्य उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की क्षमता निर्माण और आर्थिक सशक्तिकरण पर सेमिनार तथा पंचवटी घाट में सुजलाम–जल संस्कृति पर सेमिनार होगा। सायं 7 से 10 बजे रात्रि तक मुख्य पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसी दौरान खीर प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा।

द्वितीय दिवस 10 अक्टूबर 2022 सोमवार को मेला भ्रमण, प्राकृतिक खेती पर विवेकानंद सभागार में सेमिनार, सती अनुसुइया आश्रम में सुजलाम सेमिनार, मेला पंडाल में निबंध प्रतियोगिता, मुख्य पंडाल में चित्रकला प्रतियोगिता, गुरुकुल में स्वस्थ पशु प्रतियोगिता, विवेकानंद सभागार में प्राकृतिक खेती पर सेमिनार और शाम को मुख्य पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

तृतीय दिवस 11 अक्टूबर 2022 मंगलवार को मेला भ्रमण, विवेकानंद सभागार में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन, मेला पंडाल में भाषण प्रतियोगिता एवं मुख्य पंडाल में तीसरे दिवस शरद पूर्णिमा को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास शामिल होंगे।

चतुर्थ दिवस 12 अक्टूबर 2022 बुधवार को ग्रामोदय मेले के अंतिम दिन मेला भ्रमण, विवेकानंद सभागार में बाल संरक्षण अधिकार पर जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन और जनजातीय समुदाय के उत्तम स्वास्थ्य के लिए फलों की भूमिका पर सेमिनार होगा तथा मेले का समापन दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को शाम 4 बजे किया जावेगा।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

सफलता की कहानी
मध्यप्रदेश के जिला नरसिंहपुर में अधोसंरचना युक्त ग्राम पंचायत शाहपुर

मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चीचली की ग्राम पंचायत शाहपुर अपने अच्छे अधोसंरचनात्मक कार्यों की वजह से दूसरी पंचायतों के लिए उदाहरण बनकर सामने आई है। इस ग्राम पंचायत में शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे से किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत तैयार किये गये आवास, तालाब, खेल मैदान शक्कर नदी पर 10 हजार बोरियों से बनाया गया बोरी बंधान, शांति धाम, पक्की साफ– सुथरी सड़कें, उत्तम गुणवत्ता से नवनिर्मित पंचायत भवन आदि देखने लायक हैं।

सर्व सुविधायुक्त ग्राम पंचायत भवन

मनरेगा और जिला पंचायत की निधि से 14 लाख 85 हजार रूपये की लागत से नवनिर्मित पंचायत भवन बहुत अच्छी गुणवत्ता का है। इसमें सभी जरूरी सुविधायें उपलब्ध हैं। भवन का फर्श मार्बल से बनाया गया है। पंचायत भवन में कम्प्यूटर ई. कक्ष में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। सरपंचए ग्राम पंचायत सचिवए ग्राम रोजगार सहायक के अलग. अलग कक्ष के साथ एक हाल भी पंचायत भवन में तैयार कराया गया है। यहां एक अतिथि कक्ष भी बनाया गया है। इसमें बैठने एवं विश्राम की सुविधा है। सभी कक्षों के बाहर नेम प्लेट भी लगाई गई हैं। पंचायत कार्यालय में नोटिस बोर्ड लगाया गया है।

पंचायत भवन परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर उसे सुंदर स्वरूप दिया गया है। ग्राम पंचायत भवन में प्रसाधन की अच्छी सुविधा है। पंचायत भवन की दीवार पर महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर भी लिखे गये हैं। पंचायत भवन की दीवारों पर सुंदर पेंटिंग की गई है। पंचायत भवन का शुभारंभ 14 नवम्बर 2017 को हो गया

है। ग्राम पंचायत शाहपुर के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक पंचायत के कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

इस ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। पंचायत में 40 हितग्राहियों के लिए गुणवत्तायुक्त प्रधानमंत्री आवास तैयार हो गये हैं। आवासों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश हो चुका है।

जल संरक्षण हेतु बोरी बंधान

ग्राम पंचायत शाहपुर द्वारा भविष्य में जल की आवश्यकता को देखते हुए 10 हजार बोरियों से शक्कर नदी के पुल के पास बोरी बंधान बनाया गया है। इस बोरी बंधान से बड़ी मात्रा में जल राशि का संचय हो गया है। इससे अब लोगों को अपने निस्तार नहाने, कपड़े धोने आदि के लिए और मवेशियों को पानी पीने एवं गांवों की अन्य जरूरतों के लिए पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है।

ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गये बोरी बंधान से दूर तक पानी रूका है। दूर तक रूके पानी का भी उपयोग है। गर्मी के दिनों में पानी की तलाश में इस पंचायत से लगे वनक्षेत्र के वन्यप्राणी भी अपनी प्यास बुझाने के लिए बोरी बंधान तक पहुंचते हैं और पानी पीते हैं।

शांतिधाम

गांव में बनाये गये शांतिधाम में पर्याप्त छाया के लिए बड़ी संख्या में पेड़ लगाये गये हैं। यहां समीप में पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चीचली की ग्राम पंचायत शाहपुर में किये जा रहे अधोसरंचनात्मक कार्यो से ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं व लाभ मिल रहा है। इस प्रकार के अधोसंरचनात्मक कार्यो को प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतों में करवाया जा सकता है।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

प्रदेशव्यापी नशामुक्ति अभियान

संपूर्ण मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्ति हेतु ''नशामुक्ति अभियान'' के क्रियान्वयन का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को प्रदेश व्यापी नशामुक्ति अभियान का भोपाल से शुभारंभ किया गया।नशामुक्ति अभियान एक जन अभियान होगा जिसमें मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों के साथ–साथ समाजिक संगठन, धर्मगुरुजन, स्वयंसेवी एवम अशासकीय संस्थाएं भी सम्मिलित होंगे। इस अभियान के अंतर्गत युवावर्ग, बच्चों,महिलाओं पर विशेष महत्व दिया जायेगा। 2 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2022 तक चलने वाले इस अभियान में नोडल विभाग समाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन है। इस अभियान के क्रियान्वयन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं –

1. स्वैच्छिक संगठनो, धर्मगुरुओं सहित सभी वर्गों की सक्रियता बढ़ाकर जनसहभागिता को प्रोत्साहन।
2. सभी जिलों के नगरीय निकायों एवम ग्रामसभाओं में शपथ ग्रहण, रैलियां एवम मानव श्रृंखलाएं।
3. स्कूल, महाविद्यालय एवम विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिता, मैराथन एवम नुक्कड़ नाटक।
4. नशामुक्त ग्राम पंचायतों को प्रति पंचायत एक लाख रुपए की सम्मान निधि।
5. नशाग्रस्त व्यक्ति के लक्षणों के प्रति आमजन को जागरुक बनाना।
6. परिवार को नशामुक्त रखने हेतु महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान।

सहभागिता :

मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग, समस्त संगठन, स्वयंसेवी एवं अशासकीय संस्थाएं, समस्त धर्मगुरु, जनप्रतिनिधिगण, समस्त स्व–सहायता समूह, ग्राम वन समितियां, पत्रकारगण, जन अभियान परिषद की मैदानी समितियां, नेहरू युवा केन्द्र, नगर सुरक्षा समितियां, विद्यालयों (कक्षा 6 से 12) एवम महाविद्यालयों के छात्र–छात्राएं, त्रि स्तरीय पंचायत राज संस्थाएं, नगरीय निकाय, आशा, उषा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों के पूर्व पदाधिकारी गण एवं गणमान्य नागरिक इस अभियान में सहभागी हैं।

प्रस्तावित गतिविधियां कार्यक्रम :

1. वॉल पेंटिंग, रांगोली इत्यादि प्रतियोगिताएं।
2. मैराथन, नुक्कड़ नाटक के आयोजन।
3. नशामुक्ति के लिए रैलियां एवम मानव श्रृंखलाएं।
4. स्कूल, कॉलेज आदि में विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान।
5. नशे की आदत से मुक्त हुए प्रभावी एवम जिम्मेदार व्यक्तियों के व्याख्यान।
6. ग्रामसभा एवम वार्ड सभा का आयोजन कर नशामुक्ति के लिए शपथ ग्रहण।
7. मल्टी मीडिया पर जागरूकता विज्ञापन।
8. नशीली दवाओं तथा शराब के अवैध व्यापार पर पुलिस तथा आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही।
9. समाजिक न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रचार सामग्री मैदानी अमले को उपलब्ध कराना।
10. ऑटोधरिक्शा, कचरा वाहन आदि द्वारा नशामुक्ति के संदेश एवम नशामुक्ति गान का प्रसारण।
11. नशामुक्ति केंद्रों का पत्रकारों के साथ भ्रमण।
12. वेबिनार के आयोजन।
13. जिला स्तरीय समितियों में समाजिक संगठनों एवम धर्मगुरुओं द्वारा प्रस्तावित नवाचार को जोड़ा जायेगा।
14. नशामुक्ति के संदेश के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न क्षेत्रों के सेलिब्रिटीज को जोड़ा जायेगा।
15. वर्तमान में संचालित नशा मुक्ति केन्द्रों एवम नशा मुक्ति हेल्पलाइन 14446 द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा।

वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन समाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नशामुक्ति सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों से संबंधित केंद्र मध्यप्रदेश में चलाए जा रहे हैं जिनकी संख्या इस प्रकार से है –

1. नशामुक्ति सह पुनर्वास केंद्र
2. बाल नशामुक्ति केंद्र
3. Community based peer led intervention centre
4. Outreach and Drop in centres

नशामुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख गतिविधियों में ''नशामुक्त भारत अभियान'' है। नशामुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को भारत सरकार के समाजिक न्याय एवं अधिकारिता

मंत्रालय द्वारा देश में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से सर्वाधिक प्रभावित 272 जिलों में शुरू किया गया था। यहां नशे की चपेट में सबसे ज्यादा लोग पाए गए थे। इनमें से 15 जिले मध्यप्रदेश के भी हैं। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 6 करोड़ से अधिक ड्रग उपयोगकर्ता हैं जिनमें बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता 10 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य नशे की समस्या के निवारक के रूप में काम करना, लोगों को नशे की लत के बारे में जागरुक करना, इस अभियान से जुड़े विभिन्न लोगों और संस्थाओं का क्षमता निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों के साथ सकारात्मक साझेदारी और उपचार, पुनर्वास और परामर्श सुविधाओं में वृद्धि करना है।

नशामुक्ति शपथ

आज हम एकजुट होकर नशामुक्ति अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं, कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशामुक्त बनाएंगे। परिर्वतन भीतर से शुरू होता है, इसीलिए आओ मिलकर अपने मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूं कि मैं अपने प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा/करूंगी।

15 अगस्त 2020 को नशामुक्त भारत अभियान की शुरुआत के बाद से सार्वजनिक क्षेत्रों शैक्षणिक संस्थानों,सामुदायिक क्षेत्रों और सोशल मीडिया जैसे आभासी स्थानों में मादक द्रव्यों के उपयोग पर जीवंत चर्चा होने लगी है, जिसने उन लोगों को प्रेरित किया है जिन्हें परामर्श, उपचार और पुनर्वास सेवाओं की तलाश करने के लिए मदद की आवश्यकता है। इससे लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित कलंक को दूर करने के बारे में अधिक जागरुक होने में मदद मिली है।

आईये हम सब मिलकर स्वयं एवम अपने परिवार को नशामुक्त रखने की शपथ लें। जिंदगी को हां और नशे को ना कहें।

राजीव लघाटे
मु.का.अ.ज.पं.

मध्यप्रदेश ग्रामीण परिवहन सेवाः ग्रामोत्थान की दिशा में एक सार्थक प्रयास

सड़क परिवहन आर्थिक विकास, व्यापार एवं सामाजिक एकीकरण के लिये अत्याधिक महत्वपूर्ण है। एक व्यवस्थित यात्री एवं माल परिवहन की व्यवस्था से दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने एवं विकास की संभावनाओं को बढ़ाने में आवश्यक है। प्रदेश में सड़क परिवहन ही परिवहन का मुख्य आधार है।

वर्ष 2005 में राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (**MPSRTC**) को बंद करने के निर्णय के उपरांत विगत वर्षों में लोक परिवहन सेवायें मूलतः निजी तौर पर संचालित होती रही है।

प्रदेश के गाँव–गाँव में सड़के पर्याप्त निर्मित हो गई है किन्तु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आने–जाने के लिए यात्रियों को अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं हो रही थी। निजी ऑपरेटरों द्वारा उन्हीं मार्गों पर बसें संचालित की जाती थी जहाँ यात्री अधिक संख्या में उपलब्ध हो पाते थे और जहाँ उन्हें व्यवसायिक रूप से लाभ अधिक होता था परन्तु अन्य मार्गों एवं अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक रूप से लाभप्रद न होने के कारण लोक परिवहन सेवायें संचालित नहीं है।

ग्रामीण यात्री दैनिक आवाजाही हेतु मूलतः प्राइवेट छोटे वाहनों पर निर्भर है ग्रामीण परिवहन की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम करने एवं सुचारू परिवहन हेतु नई ग्रामीण परिवहन नीति आवश्यक थी।

ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सस्ती लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा ग्रामीण परिवहन नीति 2022 बनायी गई। ग्रामीण परिवहन नीति को अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषक संस्थान भोपाल (म.प्र.) के सहयोग से तैयार किया गया है। प्रस्तावित नवीन ग्रामीण परिवहन नीति के तहत Rural Transport Credit Model (RTC) मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट (Piolet Project) के रूप में किसी भी जिले में 6 माह हेतु क्रियान्वयन किया जायेगा, सफल होने पर सम्पूर्ण प्रदेश में इस सेवा का विस्तारीकरण किया जायेगा।

इसके तहत निम्नानुसार नीति तय की गई–

- जिला परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रीबस यातायात की मांग एवं रूपरेखा का सर्वेक्षण कराया जावेगा, जिससे दरों का आवश्यकतानुसार युक्तियुक्तकरण हो सके और सम्पर्कहीन क्षेत्रों में यात्री बस सेवायें प्रारंभ की जा सकें।
- उक्त सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुये जिला परिवहन प्राधिकार ग्रामीण रूटों का चिन्हांकन करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन को बढ़ावा देने के लिये पूर्णतः ग्रामीण रूटों पर संचालित बसों के लिए वर्तमान प्रतिसीट, प्रतिदिन कर प्रणाली के स्थान पर पर्याप्त रियायती दरें निर्धारित होगी।
- आवश्यकतानुसार निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सुरक्षित छोटे यात्री वाहनों को ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों में परमिट दिये जायेगें। इनकी दर पृथक से निर्धारित की जावेगी (कान्ट्रेक्टर कैरेज के मैक्सी कैब/टैक्सी कैब हेतु वर्तमान कर व्यवस्था जारी रहेगी।
- स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तर्ज पर जिले के भीतर रूट निर्धारित करने तथा परमिट देने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जावेगा, तदनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में वर्तमान गठित जिला परिवहन निगरानी समिति के

स्थान पर जिला परिवहन प्राधिकार गठन किया जायेगा जिसमें निगरानी समिति के सदस्य के साथ–साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भी सदस्य होगें ।

- जिला परिवहन प्राधिकार बस परमिट के आवेदन पत्रों की समीक्षा उपरान्त स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये ग्रामीण एवं जिले के भीतर के रूटों पर परमिट स्वीकृत करेगा । परमिट स्वीकृति उपरान्त उक्त प्राधिकार का दायित्व परमिट शर्तो का अनुपालन कराना भी होगा ।
- अर्न्तजिला एवं अर्न्तराज्यीय मार्गो हेतु परमिट राज्य परिवहन प्राधिकार से ही जारी होगें। यात्री बसों की आयुसीमा परमिट शर्तों में निर्धारित की जावेगी, जो कि ग्रामीण रूट के लिए 20 वर्ष होगी। समय–समय पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा वाहन आयु की समीक्षा कर वाहन आयु सीमा का निर्धारण किया जावेगा ।

Rural Transport Credit Model (RTC) के अन्तर्गत संचालित होने वाले वाहनों के लिये संबंधित अधिनियम एवं नियमों में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की गई है–

- मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 116–क के उपनियम (3) में शिथिलता प्रदान करते हुये ग्रामीण मार्गों पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों के संचालन का प्रावधान।
- ग्रामीण परिवहन सेवा हेतु संचालित वाहनों पर मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत देय मासिक मोटरयान कर में पूर्णतः छूट।
- ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में निरन्तर 06 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा उक्त संचालन से अर्जित किये गये Rural Transport Credit Model (RTC) के विरूद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि अगामी छःमाही में वाहन संचालक को प्रदाय ।

नवीन ग्रामीण परिवहन नीति के तहत Rural Transport Credit Model (RTC) को 26 मई 2022 से आगामी 06 माह तक के लिए पायलट प्रोजेक्ट (Piolet Project) के रूप में विदिशा जिले में ग्राम (कागपुर) से शुभारंभ किया गया। इस नीति के तहत विदिशा जिलें में 15 से 13 किलोमीटर दूरी के कुल 76 ग्रामीण मार्गों को चिन्हित किया गया है, जिसकी कुल लम्बाई 1513 किलोमीटर है इन ग्रामीण मार्गों के आसपास 546 ग्राम है जिनकी जनसंख्या लगभग 470523 है जो कि इस सेवा से लांभावित होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सहज सरल पहुँच सेवा सुविधा से ग्रामीण, स्कूली बच्चों उच्च शिक्षा हेतु शहर जाने वाले छात्रों एवं विभिन्न ग्रामीण योजनाओं से जुड़े कर्मियों, शिक्षकों में विशेष उत्साह है। इस सेवा से वह समय पर अपने कार्य सम्पन्न कर पा रहे है। ग्रामीणों के अनुसार अस्वस्थता में गंभीर स्थिति में, बारिश में वाहन उपलब्धता के लिये भटकना पड़ता था शहर जाने के लिये साधन खोजने पड़ते थे किन्तु अब इस नयी ग्रामीण परिवहन सेवा ने उनके सभी कष्ट दूर कर दिये है।

यह अभूतपूर्व ग्रामीण परिवहन सेवा है सुदूर ग्रामों तक इसका लाभ ग्रामीण सहजरूप से ले पा रहे है। निष्चित ही शासन की इस पहल से भविष्य में ग्राम विकास, ग्रामीण विकास, ग्राम अर्थ व्यवस्था की प्रगति में अभूतपूर्व परिवर्तन आयेगें।

प्रतिमा शुक्ला,
मु.का.अ.ज.पं.

बैतूल की जनपद पंचायत आमला की ग्राम पंचायत बोरदेही में प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर स्ट्रक्चर से निष्काषित अपशिष्ट जल का शुद्विकरण कार्य

संक्षिप्त विवरण –

बैतूल जिले की जनपद पंचायत आमला की ग्राम पंचायत बोरदेही, जिसमें अधिकांश घरों में व्यवसायिक दुकानें है, एवं घरों से ग्रे–वाटर, ब्लैक–वाटर सीधे नाली के माध्यम से छोड़ दिया जाता है। इस प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर स्ट्रक्चर के माध्यम से कुल 181 घर के 865 सदस्यों के उपयोग से निकलने वाले निष्काषित अपशिष्ट जल को शुद्विकरण का कार्य इस संरचना द्वारा किया जा रहा है।

तकनीकी मापदण्ड –

प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर की संरचना में सर्व प्रथम सिल्ट चेम्बर का निर्माण किया गया, जिसमें ब्लैक, ग्रे–वाटर नाली/पाईप के माध्यम से नाली से होता हुआ आता है। इससे कनेक्टेट सेटलर टैंक जिसका माप (5'3'1'5) क्यूबिक मीटर का निर्माण किया गया है, जिसमें दो भाग है, प्रथम भाग में दूषित पानी के साथ आनेवाला ठोस, बारिक कचरा नीचे सेटल हो जाता है। तथा पानी छनते हुये दूसरे भाग में चला जाता है, और इसी तरह दूसरे भाग का भी कार्य ठोस, बारिक कचरे को सेटल कराते हुये, पानी छनते हुये सेटलर टैंक के आउटलेट के माध्यम से ग्रेवल फिल्टर टैंक के में चला जाता है।

इस संरचना में छः ग्रेवल फिल्टर टैंक बने है, जिसमें से चार फिल्टर टैंक में प्राकृतिक पद्वति की तरह 20 एवं 40 एमएम गिटटी मिक्स करकें टैंक में डाली गई, जो कि पानी को छानने का कार्य कर रही है। अंत के दो टेंकों में जलीय प्रजाति के पौधे जैसे– केना (कैली), रोपित किये गये है। जो कि, पानी को छानने का कार्य कर रहे है। इस तरह अंत में पानी पूर्ण रूप से साफ एवं स्वच्छ निकलता है। इस प्लांट के अतंर्गत प्रतिदिवस लगभग 865 सदस्यों के 34000 लीटर गंदे पानी सीधे भैसाई नदी में मिल कर नदी के पानी को प्रदूषित करता था। जो कि इस संरचना बबने के बाद नदी में केवल फिल्टर होने के पश्चात साफ पानी ही मिल रहा है।

संस्कार बावरिया
मु.का.अ.ज.पं.

स्व–सहायता समूह के माध्यम से नलजल योजना के संचालन के सफलता की कहानी

जनपद पंचायत आमला की ग्राम पंचायत रमली जो कि, विकास खण्ड मुख्यालय से 03 किलोमीटर दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित है। ग्राम पंचायत रमली में एक ही ग्राम है जिसकी जनसंख्या 2160 एवं कुल परिवार 490 है। यहॉ के निवासियों का मूख्य व्यवसाय कृषि, एवं मनरेगा कार्यो में की जाने वाली मजदूरी है। पूर्व में ग्राम पंचायत में पेयजल की व्यवस्था पेयजल कूप एवं हेण्डपम्प के द्वारा की जाती थी।

वर्तमान में ग्राम पंचायत नलजल योजना से जुड़ी है। ग्राम पंचायत रमली में कुल 370 नल कनेक्शन है, जिसका संचालन ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा किया जाता था। ग्राम पंचायत अपने स्तर से पम्प संचालक एवं वॉलमेन की व्यवस्था करके उन्ही के सहयोग से संचालन सुधार एवं कर वसूली का कार्य कर रही थी।

ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही नलजल कर वसूली में आ रही कठिनाईयाँ

1. कर वसूली समय सीमा में नही होना –

नलजल योजना संचालन की कमान मुख्य रूप से सरपंच ग्राम पंचायत के हाथों मे थी, जिस कारण कई बार ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई जिसमें सरपंच के विपक्षियों व अत्यधिक नजदीकी परिजनों द्वारा नियमित रूप से नलजल कर का भुगतान ग्राम पंचायत में नही किया जाता था। जिससे कर वसूली कम हो पाती थी।

2. कार्य की अधिकता –

ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव ग्रामीण क्षेत्र में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यस्तता होने के कारण नलजल योजना का सूचारू रूप से संचालन नही हो पाता था, जिसके कारण जलकर की वसूली बाधित होती थी।

3. **नलजल योजना के संचालन के दौरान हो रही टूट–फुट एवं मरम्मत में विलम्ब –**

ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव ग्रामीण क्षेत्र में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यस्तता होने के कारण पाईप, वॉल्व, मोटर के टूट–फुट एवं मरम्मत समय पर नही हो पाती थी, जिसके कारण ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पडता था, एवं योजना के प्रति असंतोष जागरित होता था जो कि, कर भुगतान में नकारात्मक रूप से परिलक्षित होता था।

उपरोक्त कारणों से ग्राम पंचायत नलजल योजना की कर वसूली अत्यंत कम हो पाती थी जिससे इसका संचालन एवं समय से बिजली बिल भुगतान नही हो पाता था, जिससे समय–समय पर विद्युत विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन काटा गया, जिससे योजना संचालन में असुविधा होती थी।

नलजल योजना संचालन हेतु नवीन व्यवस्था में समूह ने संभाली नलजल योजना संचालन की कमान

ग्राम पंचायत रमली जनपद आमला में कुल 15 महिला स्व–सहायता समूह है, जो कि किसी न किसी आजीविका संबंधित गतिविधियों से जुड़े है। नलजल योजना संचालन का प्रस्ताव समस्त समूह के समक्ष रखा गया। सभी ने सर्व सहमति से जय मॉ लक्ष्मी स्वसहायता समूह को नलजल संचालन का कार्य क्रियान्वयन करने हेतु ग्रामसभा के समक्ष प्रस्ताव पारित किया। जय मॉ लक्ष्मी स्वसहायता समूह में कूल 11 महिला सदस्य है, जिनकी अध्यक्ष श्रीमति बाली ठाकरे है, एवं सचिव श्रीमति अनिता बारस्कर है।

समूह का प्रशिक्षण –

नलजल योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन समूह के लिये एक नवीन कार्य था, जिसके लिये जनपद स्तर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लाक प्रबंधक एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिक के उपयंत्री के माध्यम, से समूह को प्रशिक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आमला के नेतृत्व में प्रदान किया गया।

प्रारंभिक प्रयास –

- जनपद स्तरीय दल द्वारा समूह की महिलाओं को ग्राम की भौतिक स्थिति के साथ–साथ पेयजल के प्रारंभिक बिन्दु, पानी टंकी, पेयजल कूप तथा मुख्य वॉल्व का अवलोकन के साथ–साथ परिचालन के बारे में समझाईश दी गई।
- जनपद स्तरीय दल व ग्राम पंचायत सचिव के साथ जय मॉ लक्ष्मी स्वसहायता समूह के अध्यक्ष/सचिव व समूह के अन्य सक्रिय महिलाओं के साथ घर–घर भेट करते हुये, कर वसूली का कार्य प्रारंभ किया गया।

- पुराना बकाया बिल की वसूली के संबंध में महिला स्व–सहायता समूह के सहयोग के लिये जनपद स्तर से संबंधित सेक्टर अधिकारी एवं उपयंत्री व राजस्व विभाग के पटवारी को संलग्न कर विशेष नलजल कर वसूली केम्प का आयोजन कर नलजल कर व अन्य कर में अपेक्षा से अधिक उपलब्धि हासिल की गई।
- ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाले सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में बकाया दारों के नामों का वाचन किया गया, साथ ही कर वसूली के लिये जागरूक किया गया।

नलजल कर वसूली का विवरण –

ग्राम पंचायत रमली द्वारा नलजल योजना जय मॉ लक्ष्मी स्वसहायता समूह को हस्तांतरित की गई, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (ग्राम पंचायत) द्वारा स्व–सहायता समूह से अनुबंध किया गया, अनुबंध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का बिन्दुवार अवलोकन, वाचन व पालन के संबंध में कार्यवाही सम्पादित की गई।

योजना प्रारंभ से नलजल कर वसूली की बकाया राशि रूपये 62345/– थी। विशेष केम्प व अभियान के माध्यम से राशि रूपये 36400/– पुरानी बकाया कर वसूली के रूप में ग्रामीणों से जमा कराई गई। नवीन कर वसूली के रूप में राशि रूपये 38400/– वसूले गये। इस प्रकार जलकर के रूप में राशि रूपये 74800/– जमा की गई।

तुलनात्मक विश्लेषण लाभ :–

1. महिला सशक्तिकरण –

नलजल योजना का संचालन तथा क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम पंचायत से शासन के निर्देशानुसार जय मॉ लक्ष्मी स्वसहायता समूह रमली को प्रदाय किये जाने से ग्राम पंचायत रमली में महिलाओं की भागीदारी से महिलाओं में आत्मविश्वास व साहस के भाव जागृत हुये है, यह शासन की महिला सशक्तिकरण की एक अनुठीपहल साबित हुई है।

2. आर्थिक लाभ –

ग्राम पंचायत द्वारा नलजल योजना के संचालन के दौरान जलकर की वसूली लगभग 8000/– से 9000/– रूपये तक ही प्रतिमाह प्राप्त होती थी, जो आज बढ़कर औसतन 19000/–रूपये प्रतिमाह तक पहुच गई है, इससे ग्राम पंचायत व स्व–सहायता समूह को आर्थिक लाभ की प्राप्ति हुई है।

3. योजना का सूचारू संचालन व क्रियान्वयन –

पूर्व में ग्राम पंचायत रमली द्वारा नलजल योजना का संचालन व क्रियान्वयन आर्थिक तथा सहभागिता अभाव के कारण ठीक से नही हो पाता था, परन्तु वर्तमान में ग्राम के जय मॉ लक्ष्मी स्वसहायता समूह के नेतृत्व के कारण ग्राम पंचायत की लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होने से योजना का संचालन व क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो रहा है।

चंद्रेश कुमार लाड़,
संकाय सदस्य

1

"हमारा गांव भी बनेगा तालो का ताल"

प्राब्लम स्टेटमेंट :

ग्राम कलाखेड़ी की मुख्यालय से दूरी लगभग 25 किलो. है, इस गॉव की आबादी लगभग 1200 है , यहॉ पर लगभग 50 कुएं , 65 ट्यूबवेल है , इस गॉव में जल संरक्षण के कार्य से पूर्व प्रारंभ होने के पहले लोग शासन के लाभांवित योजनाओं से वंचित थे, लेकिन प्रोजेक्ट प्रारंभ होने के पश्चात् गाव में सभी क्षेत्र में जागरूकता आई है और गांव में कई बार ग्राम सभाओं का आयोजन भी हुआ। प्रारंभ होने के पूर्व में गांव का वाटर लेबल काफी कम था किसानों को पानी पलेवा के समय पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता था ।

ग्राम में जल स्तर बढ़ाने के लिए प्रारंभ में सर्वप्रथम पहाड़ियों पर कंटूर टंच का कार्य किया गया। जिससे कि पानी के बहाव को कम कया गया इसके पश्चात बोल्डर चेक डेम का निर्माण किया गया परकोलेषन तालाब बनाए गए फार्म पौंड एवं संकल पौड का निर्माण किया गया।

परिणाम :

यूं तो गांव में कुए और तालाब काफी मात्रा में थे किंतु 50 कुए व 65 ट्यूबवेल ऐसे है जिलको कि सीधे रूप में फायदा हुआ है इन जल श्रोतो के जल स्तर में काफी बड़तरी हुई है जिसके चलते किसानों कि भूमी में सीधे रूप में फायदा हुआ हैं गांव के किसानों को इससे के चलते काफी लाभ हुआ इसके अतिरिक्त बाकी

किसानों को भी लाभ प्राप्त हुआ हैं। इन किसानों के जल श्रोतो कि स्थिति पूर्व यह थी कि इनके जलस्त्रोतो में मात्र 5 से 7 घण्टे मोटर चलती थी, तथा इनकी फसलो का औसत 10 से 20 क्विटल प्रति हेक्टर था, तथा अपनी भूमि पर पानी की कमी के कारण आधी भूमि में चना मसूर तथा आधी भूमि में गेहूॅ की फसल लेते थे , लेकिन जल संरक्षण के कार्यो के पश्चात् कृषकों की भूमि में आश्चर्य चकित परिर्वतन हुए, इन किसानो के जलस्त्रोतो में अब 12 से 15 घण्टे मोटर चलती है। सिंचाई पर्याप्त मात्रा में हों जाती है , तथा इनकी फसलो का जो औसत बड़ा है , वहा 25 से 30 क्विटल प्रति हेक्टर पैदावार में बढोतरी हुई है , तथा किसान अपनी इच्छा अनुसार बोनी करता है , खासकर गेहूॅ की फसल अधिकांश किसान लेने लगे है , साथ ही सब्जियो को भी कुछ किसान अपने खेतो में लगाने लगे है , जिसकी पैदावार भी काफी अच्छी होती है ।

वर्तमान स्थिति यह है कि रबी की फसल में जल संरक्षण के कार्यो से पूर्व फसल में केवल एक ही पानी दे पाते थे , और कभी – कभी तो वह भी कब वर्षो के होने के कारण नहीं दे पाते थे , किन्तु जल संरक्षण में विभिन्न प्रकार की सरंचनाओं के निर्माण के पश्चात् जल स्तर में बढोतरी हुई है , व रबी की फसलो में किसान 2 से 3 बार पानी दे देता है , जिससे गॉव के किसानो का जीवन स्तर व आर्थिक स्तर उपर उठा है , व किसान आत्मनिर्भर बनता दिखाई दे रहा है , जल मित्र का मुख्य कार्य जलस्त्रोतो का लेबल हर माह लेना होता है , हर माह जो वाटर लेबल लिया जाता है , वह चौका देने वाला परिणाम है , जल संरक्षण के कार्य से पूर्व से जिन जलस्त्रोतो में 8 से 10 फिट पानी रहता था , अब उन जलस्त्रोतो में लगभग 14 से 18 फिट पानी देखा जा सकता है, तथा जो टयूबवेल पहले 1 या 1/2 चलती थी, अब वह 1 1/2 से 2 इंच चलने लगी है। गॉव के किसानो के साथ – साथ गॉव के समग्र विकास को लेकर भी काम किया गया , जिसमें विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी समय – समय पर दी गई, व गांव में स्वसहायता समूह की जानकारी किसी को नहीं थी, जल संरक्षण के कार्य से पूर्व के अन्तर्गत ग्राम कलाखेड़ी में 4 महिला स्वसहायता समूह गठन किया गया, जिनका बैंक में खाता खुलवाकर बचत कार्य से जोड़ा गया , इन स्वसहायता समूहो को आत्मनिर्भर बनाने स्वरोजगारो से जोड़ा जा रहा है , इसके अतिरिक्त गॉव में साफ– सफाई को लेकर भी अभियान चलाया जा रहे है, स्कूल में बच्चो के साथ स्वस्थता अभियान भी चलाया गया , जल संरक्षण आने के बाद ग्रामवासियों का सामाजिक व आर्थिक स्तर में बढोतरी हुई है, व लोग अपनी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही को समझने लगे है ।

इस गॉव में वाटर लेवल बढने के साथ–साथ आस पड़ोस के गॉव का जलस्तर बढा। जिससे मोटीवेट होकर लोगों ने गॉव में ग्राम सभा में की जा रही बैठकों में इस उपलब्धि की चर्चा की एवं तय किया कि जल संरक्षण के किये गए कार्यों को हमारे गॉव में भी कराए जाने चाहिये।

आशीष कुमार सोनी,
प्रोग्रामर

मुझे मिला राजमिस्त्री प्रशिक्षण से रोजगार

श्री राधेश्याम नर्गेश, ग्राम भवानीपुर ग्राम पंचायत आसपुर विकास खंड कुक्षी जिला धार का निवासी है। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत कुक्षी से पता चला कि ग्राम पंचायत आवली विकास खंड कुक्षी में राजमिस्त्री प्रशिक्षण 45 दिन का होने वाला है जिसमें 45 दिन की मजदूरी भी मिलेगी और हमें राजमिस्त्री का काम भी सिखाया जायेगा तो मैंने भी अपना नाम जनपद पंचायत में लिखवा दिया और मैंने 45 दिन का प्रशिक्षण पूर्ण किया व परीक्षा भी पास कर के सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया।

प्रशिक्षण के बाद बदली मेरी जिन्दगी

राजमिस्त्री प्रशिक्षण के पहले श्री राधेश्याम नर्गेश कोई काम नहीं आता था में वह बेरोजगार थे। उनके द्वारा 45 दिन तक में लगन व मेहनत कर से प्रशिक्षण लिया गया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें 5 लोगों का ग्रुप बनाकर सिखाने के लिए 1 डेमोस्टेटर सर थे (जगमोहन सिर्वी)उनके द्वारा 45 दिन तक अच्छे से समझाया गया कि PMAY-G अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे घर बनाया जाता है और किस–किस औजार व सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने हमें प्रतिदिन 1 घंटा तक पहले तो क्लास में बैठाकर पढ़ाया व बाद में हमारे ग्रुप को जो प्रधानमन्त्री आवास मिला उस पर काम करने ले जाकर अभ्यास कराया वहां भी छोटी–छोटी बातें समझाते हुये मुझे और मेरे साथी राजमिस्त्रियों को अच्छे ढंग से काम को सिखाया व हमारे ग्रुप के द्वारा व डेमोस्ट्रेटर सर के सहयोग से हमने प्रधानमन्त्री आवास को 45 कार्यदिवस में पूरा किया।

आगे उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद मैंने राजमिस्त्री का काम करना शुरू किया जिसकी आय से मैं व मेरे परिवार का पालनपोषण चलने लगा। जहा मैं पहले मुश्किल से 150 रूपये प्रतिदिन मजदूरी पर काम करता था और अब प्रशिक्षण के बाद में राजमिस्त्री बनकर 400 रूपये प्रतिदिन मजदूरी पर काम करने लगा। धीरे–धीरे मैं छोटे–मोटे ठेके भी लेना शुरू कर दिया जिससे मेरे परिवार की आय में बढ़ोत्तरी हुई।

उन्होंने बताया कि इन सभी का कार्य में प्रशिक्षण टीम व जनपद पंचायत के सहायक यंत्री मेडम, ब्लाक समन्वयक, सब इंजीनियर सर व हमारे ग्रुप के डेमोस्टेटर सर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया व मुझे मजदूर से राजमिस्त्री बनाया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2018 में हुआ था और जनपद में पहला प्रशिक्षण था जिसमें 35 राजमिस्त्रियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था और इस प्रशिक्षण में 7 डेमोस्टेटर थे जिनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था हमारी थर्ड पार्टी एसेसमेन्ट के तहत परीक्षा लेने के लिए दिल्ली से सर भी आये थे।

शिव कुमार सिंह,
प्रोग्रामर

मेसन प्रशिक्षण से आवास के लाभार्थी एवं मेसन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन

मेसन प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण चयनित हितग्राहियों को डेमोस्ट्रेटर एवं चयनित राजमिस्त्रीयों द्वारा मॉडल आवास एक मुहिम के तौर पर बनवाये जा रहे है जिससे ऐसे आदर्श मॉडल आवास के द्वारा अन्य प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण बनवाये जा रहे है जिससे सभी आवास अच्छे एवं गुणवत्तापूर्ण बनाये जा सके ताकि हितग्राही उसका सार्थक प्रयोग कर सके इस आवास योजना में हितग्राही को 1 लाख 20 हजार रूपये की राशि एवं मनरेगा से 90 दिवस की मजदूरी लगभग 18 हजार रूपये एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिये 12 हजार रूपये की राशि दी जाती है।

ऐसी एक कहानी टीकमगढ जिले के जनपद पंचायत पलेरा की ग्राम पंचायत लारौन है जिसमें पात्र हितग्राही श्री काशीराम चढार पिता श्री मख्खन चढार है इस आवास योजना के चल रहे राजमिस्त्री प्रशिक्षण के तहत इनके आवास में 05 राजमिस्त्री राजेन्द्र चढार, पप्पू अहिरवार, धनीराम कुशवाहा, गिरीश मोहन खरे, रामकिशोर चढार एवं डेमोस्ट्रेटर राजेश कुमार रिछारिया द्वारा निमार्ण कार्य मेसन प्रशिक्षण देकर कराया गया है एवं हितग्राही की समस्त किस्त जारी की जा चुकी है एवं इनके आवास कार्य इनका आवास कार्य अवधि फरवरी 2018 से अप्रैल 2018 में पूर्ण हो चुका है।

इस मेसन प्रशिक्षण होने के कारण कार्य कर रहे मेसन के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है मेसन के द्वारा बताया गया कि पहले मेसन का कार्य करने पर 200 से 250 रूपये तक मजदूरी मिलती थी परन्तु इस प्रशिक्षण के उपरान्त मेसन कार्य सीखने एवं गुणवत्ता पूर्ण मापदण्ड अनुसार शुद्वता पूर्ण कार्य सीखा है जिससे मेसन की निर्माण कार्यो में मांग बढी है एवं दिन की मजदूरी में थी बढोत्तरी हुई है जिससे इनके परिवार की आजीविका में बेहतर परिणाम दिखाई दे रहे है एवं निरंतर कार्य मिल रहा है।

हितग्राही द्वारा बताया गया कि कठिनाईयो भरा जीवन आमदनी इतनी की 02 वक्त की गुजर वसर हो रही थी रहने के लिए पुराना टपरा था जिसमें शुद्व हवा एवं रोशनी की व्यवस्था न होने के कारण परेशानियॉ होती थी पहले आवास न होने के कारण बारिस से होने वाली परेशानियों से जूझना पडता था खुद का कोई आवास नहीं था इस महगाई के दौर में गरीब परिवार के लिये घर बनवाना एक मुश्किल कार्य है लेकिन आवास स्वीकृत होकर पूर्ण हो चुका है हितग्राही स्वयं के आवास में रहकर खुशहाली जीवन व्यतीत कर रहे है एवं बारिस से होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल जायेगा और हितग्राही को अब आर्थिक रूप से जो परेशानिया थी वह भी हल हो चुकी है एवं आवास में उन्हें जब प्रकाश एवं शुद्व हवा की समुचित व्यवस्था है एवं उनके जीवन स्तर मे सकारात्मक सुधार हुआ है हितग्राही काशीराम चढार ने बताया कि गरीब परिवार के लिये सपनों का घर होना इस योजना के तहत मुमकिन है ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से बहुत हद तक सहायता राशि प्राप्त होती है एवं हितग्राही ने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद देते हुये कहा कि ये गरीबो के हितेषी है आज हम जैसे लाखों लोगों के स्वयं के घर का सपना पूर्ण हुआ है आज हमारे सिर पर पक्का छत है।

लवली मिश्रा,
संकाय सदस्य

कार्यशैली से बिजावर जनपद पंचायत जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास

जनपद पंचायत बिजावर का दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। जिसके तहत प्रोत्साहन स्वरूप भारत सरकार के द्वारा 25 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा बीते 2 वर्षों में बिजावर जनपद पंचायत ने सुंदरीकरण, जल संरक्षण, स्वच्छता और अन्य मापदंडों के अनुसार उत्कृष्ट कार्य किया और बिजावर जनपद पंचायत का मॉडल बनाया गया । जनपद पंचायत के सीईओ अखिलेश कुमार उपाध्याय द्वारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों के निर्देशन में दूरगामी सोच के साथ कार्य किए गए।

जनपद पंचायत प्रांगण में आजाद पार्क इसकी एक विशेष मिसाल बना। यहां स्वच्छता और प्रकृति संरक्षण के उद्देश कई क्यारियों का निर्माण कराया गया जिसकी सुरक्षा के लिए महत्वकांक्षी योजना तैयार कर क्यारियों के नाम क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों के नाम से रखे गए, जिसका सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिला और जनपद पंचायत कार्यालय सौदर्यीकरण और सुरक्षा की मिसाल बना साथ ही अनुपयोगी मैदान के समुचित अपयोग की योजना तैयार की गई और कर्मचारियों एवं अतिथियों के बैठने हेतु पार्क तैयार किया गया जहां सुंदरता और स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा कार्यालय के ठीक बगल में अनुपयोगी जगह को भी सुविधाजनक कैंटीन बना कर तैयार किया जा रहा है जिससे स्व सहायता समूह के सदस्यों को रोजगार भी मिले और यहां आने जाने वालों को स्वादिष्ट अल्पाहार भी उपलब्ध हो सके। जल संरक्षण के लिए भी कई स्थान चयनित कर सोखता गड्डे बनाए गए जिससे आसपास के जल का संरक्षण हो साथ ही जल स्तर भी बना रहे। पूरे जनपद पंचायत कार्यालय में निगरानी और व्यवस्था के लिए सीसीटीबी कैमरे भी लगाए गए जिससे काफी हद तक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन देखे गए। सीईओ अखिलेख कुमार उपाध्याय की कार्यशैली और उचित समन्वय के चलते बिजावर जनपद कार्यालय को दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयन किया गया। जिसके तहत पुरस्कार स्वरूप 25 लाख रूपये भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाऐंगे।

पुरस्कार पाने वाला संभाग का दूसरा और जिले का प्रथम कार्यालय बना जनपद बिजावर

60 ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने वाला छतरपुर जिले का पहला कार्यालय बना। जिससे अब बिजावर जनपद पंचायत अन्य जनपद पंचायतों के लिए मॉडल बन गया है। मापदंडों के अनुसार प्रदेश के जिले,जनपद पंचायत कार्यालय और ग्राम पंचायतों को क्रमशः 50 लाख 25 लाख और 10 लाख की राशि पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। इसी के तहत विभिन्न मापदंडों पर खरा उतरने के चलते और बिजावर जनपद पंचायत के उसकी कार्यशैली व उचित प्रबंधन को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। जनपद पंचायत के सीईओ अखिलेश कुमार उपाध्याय ने इस पुरस्कार का श्रेय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं जनपद पंचायत के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों और पंचायत सचिवों ग्राम रोजगार सहायकों को दिया है। उन्होंने कहा कि शासन की गाइडलाईन अनुसार इस राशि से जनपद पंचायत को और अधिक सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाएगा साथ ही शासन की मंशा अनुरूप जनहितेषी कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

आर.पी. खरे,
संकाय सदस्य

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बढ़ते कदम

मध्यप्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत लगभग 387000(तीन लाख सत्यासी हजार) से अधिक महिलाओं के समूह गठित किये गये।

एसआरएलएम के अन्तर्गत गांव में तीन संगठन कार्य करते है स्व.सहायता समूह ग्राम संगठन(व्ही.ओ) एवं संकुल स्तरीय संगठन (सीएलएफ) तीनों संगठन का मूल कार्य गांव में रहने वाली महिलाओं को समूह के माध्यम से संगठित कर सशक्त करना है। जिससे महिलायें आजीविका के माध्यम से अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाकर सशक्त अर्थात मजदूरी छोड़कर स्वयं का रोजगार कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लायें इस कार्य में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका महती भूमिका निभा रहा है एसआरएलएम द्वारा गांव –गांव में परिवार की दीदीयों (महिलाओं) को जोड़कर बैंक के माध्यम गांव में ही लघु उद्योग, छोटे व्यवसाय से जोड़कर समूह की दीदीयों के परिवार की आय में वृद्धि कर सशक्त कर दीदीयों के जीवन स्तर में सुधार ला रहे है।

समूह की महिलाओं का ग्राम पंचायत से अनुबंध कर नल जल योजना संचालित कर जल कर वसूल

कर ग्राम पंचायत की स्वयं की आय में वृद्धि कराकर जलकर एवं नलजल संचालन से प्राप्त कमीशन से अपने ही गांव में रोजगार प्राप्त कर अपने जीवन स्तर में सुधार ला रही है

प्रदेश में 5000 (पांच हजार) आबादी वाले 50 गांवों में नल जल योजना की जिम्मेदारी स्व सहायता समूहों को सोपी जा रही है।

स्व.सहायता समूह दीदीयां प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट के कार्य करने का दायित्व दिया जा रहा है प्लास्टिक वेस्ट ग्रामीण सड़क बनाने के काम उपयोग लाया जायेगा ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण इस में कार्य योजना बना रही है।

प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट के अन्तर्गत प्लास्टिक वेस्ट मनेजमेंट हेतु समूह को सीएलएफ (सामुदायिक निवेश पूंजी) देकर कार्य कराया जायेगा।

गांव में ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला निर्माण कर गौशाला संचालन कार्य स्थानीय स्व. सहायता समूह को सौपा जायेगा एवं बैकों के माध्यम से स्व.सहायता समूहों की दीदीयों को गाय पालन (पशुपालन) बकरी पालन, भैस पालन, सुअर पालन, निजी राइस मिल, वर्मी कम्पोस्ट विक्रय, पोशाक बनाना, मनिहारी अन्य छोटे–छोटे व्यवसाय से संवहनीय आजीविका से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है; गांव की पड़त भूमि में हल्दी,धान की खेती एवं गौशालओं को लाभदायी व्यवसाय बनाने जैसे कार्य कराकर दीदीयों के जीवन स्तर में बदलाव एसआरएलएम ला रहा है।

आदिवासी बाहुल्य जिला अनुपपुर के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम सोनियामार की चंपासिंह ने कृषि सखी मास्टर ट्रेनर के रूप में अब तक 5500 परिवारों को वर्मी कम्पोस्ट बनाना (केचुआ खाद्य) एवं वर्मी खाद्य विक्रय का प्रशिक्षण देकर आजीविका सुद्दढ करने का मार्ग दिया निश्चित चंपा सिंह का कार्य सराहनीय है चंपासिंह स्वयं वर्मी एवं जैविक खाद्य कीटनाशक तैयार कर बिक्री का कार्य आज चंपासिंह की वार्षिक आय 2. 97 रू (दो लाख सतान्वे हजार रूपये) है चंपासिंह को जिला अनूपपुर एवं भोपाल में सम्मानित किया जा चुका हैं

मध्यप्रदेश के सिहोर जिले की ग्राम पंचायत विल्किसगंज ने ग्रामीण विकास के आदर्श मानक स्थापित करके साथ ही वर्ष 2041 तक समुचित का मसौदा (कार्य योजना) तैयार की है।

ग्राम पंचायत विल्किगंज स्व.सहायता समूहों को डेयरी एवं डेयरी प्रोजक्ट प्लांट भी प्रस्तावित है। समूह द्वारा जैविक खाद्य का प्लांट महाराष्ट्र बी.एन.बी. और ग्रामीण प्लांट में कचरे में 15 दिवस में खाद्य तैयार हो रही है;

यह काम स्व. सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है पंचायत यह खाद्य पांच रूपये किलो में विक्रय कर रही है।

जिला श्योरपुर के अमरूद स्व.सहायता समूह के माध्यम से अमरूद जूस का प्लांट लगाकर आजीविका ब्रांड से पेकिंग कराकर बाजार में विक्रय करने की योजना है इसव हेतु 1500 हेक्टयर में श्योरपुर किसानों को अमरूद के पौधे लगाकर बगीचे को विकसित कियाजा रहा है। ''एक जिला एक उत्पाद'' योजना के अन्तर्गत श्योरपुर को अमरूद से निकालने एवं पैकिंग कर जूस बेचने की योजना है।

मध्यप्रदेश के जिला सिवनी की जनपद पंचायत छपारा सीताफल के लिये प्रसिद्ध है महादेव महिला आजीविका ग्राम संगठन खैरमटा कोल के ग्राम भूत घंधानी द्वारा प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले छीताफल ग्राम संगठन की महिलाओं के द्वारा क्रय कर ग्रेडिंग कर छीताफल की पेकिंग जिले के बाहर बेचा जा रहा है प्रदेश में स्व.सहायता समूहों का लगभग 23000 करोड का टर्न ओवर है ;

समूह अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 6000 समूहों की महिला सदस्यों द्वारा 1200 सिलाई केन्द्रों द्वारा 63 लाख तिंरगे बनाये गये एवं विक्रय किये गये यह हर घर तिरंगा अभियान के अन्तर्गत किया गया।

समूहों के माध्यम से महिलाओं का संस्थागत विकास के लिये एसआरएलएम सतत् प्रयास कर रहा है। समूहों को चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड) सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ) आपदा कोष (वीआरएफ) एवं बैंक लिंकेज के माध्यम से गरीब परिवारों की छोटी,बडी आर्थिक आवश्यकतों की पूर्ति की जाती है।

शासन की अन्य योजनाओं से समूहों का समन्वय कर पात्रानुसार लाभ दिलाया जाना।

समूहों के सदस्यों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, परिसम्पतियों की बीमा सुविधा प्रदाय करने में सहयोग करना। ग्रामीण युवाओं को रोजगार, स्व रोजगार हेतु कौशल आधारित प्रशिक्षण कराकर रूचि अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना। बैंक से ऋण प्राप्त कर स्व सहायता समूह की दीदी रोजगार कर प्रतिमाह तीन से चार हजार मुनाफा प्रतिमाह कमा रहा है।

मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी का कार्य भी समूह की दीदी कर रही इसी प्रकार महिलाओं द्वारा आजीविका एम्सप्रेस सवारी वाहनों का संचालन दोहतर ढंग से किया जा रहा है।
गांव के विकास में महिलाओं की भूमिका मध्यप्रदेश में स्व सहायता समूहों की दीदीयां बोडिया तोड़कर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।

गांव दीदी कैफे (रेस्टारेंट) चला रही है, 134 दीदी कैफे मध्यप्रदेश में सफलतापूर्वक चल रहे है।
63000 (तिरेसठ हजार) से अधिक बाहिने सिलाई में निपुण हो चुकी है। जिसमें से 12000 बहिने ने सिलाई व्यवसाय कर अपने परिवार को चला रही है।

ग्रामीणों क्षेत्रों में आजीविका गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के लिये प्रदेश में पिछलें वर्ष लगभग 1500 करोड़ रूपयें का ऋण बैकों के माध्यम से बहिनों को दिया गया।
8300 महिलओं को कम लागत कृषि एवं जैविक खेती पर प्रशिक्षित किया गया।

बहिनों ने मास्टर कृषि सी आर पी के रूप में केवल अपने प्रदेश वल्कि हरियाणा,उत्तरप्रदेश पंजाब में सेवायें देकर पहचान बनाई है।

सभी बहिनों का मानना हे कि महिलायें ठान ले तो कुछ भी कर सकती है मध्यप्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका के अमले की मेहनत एवं सतत् प्रयास में गांवो की महिलाओं स्व.सहायता समूहों से जोड़कर बैंक एवं ग्राम संगठन एवं सीएलएफ के माध्यम से आर्थिक मद्द देकर गांव में ही रोजगार देकर पलायन जैसे समास्या एवं गांव का उत्पाद कैसे शहर में पहचान बनावें यह सफलतम प्रयास किया गया है। जेण्डर जैसे संवेदनशील जैसे मुद्दों को महिला एवं पुरूष में भेदभव समाप्त करने का भी प्रयास जारी है निश्चित मध्यप्रदेश एसआरएलएम के बढ़ते कदम है।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य